



www.agrabharat.in

नई सोच का अखबार



दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

वर्ष: 19

अंक: 111

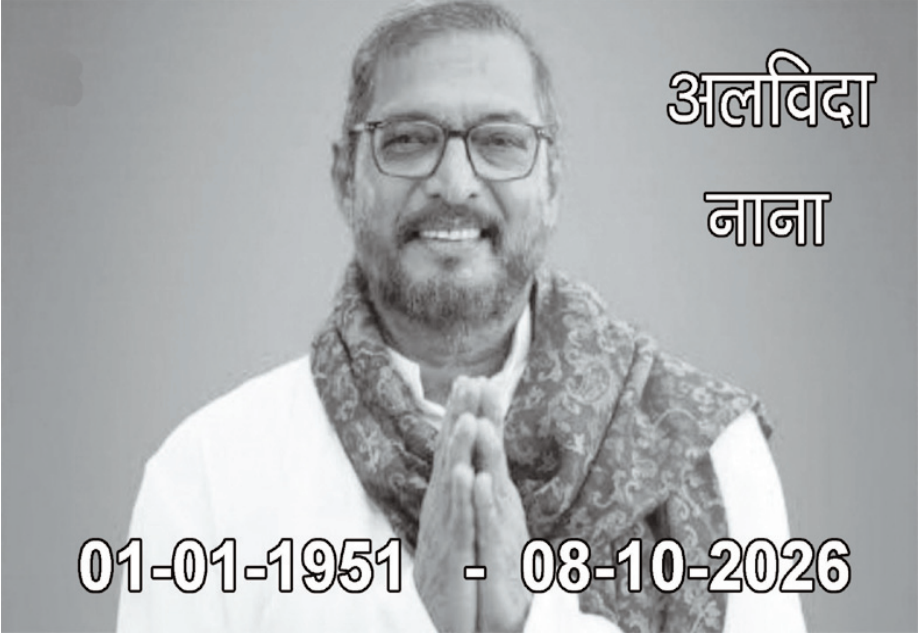
आगरा, शुक्रवार 08 अक्टूबर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 ₹.

# दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन

गंभीर कार्डियक अरेस्ट : गोवा में ली अंतिम सांस

**जन्म- 1 जनवरी 1951**  
**मृत्यू- 8 अक्टूबर 2026**  
**गोवा(ए)।** हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह उनके गोवा स्थित आवास पर निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 75 वर्षीय अभिनेता को गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और सुबह करीब 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनकी जान बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया। इसके बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। डॉक्टर के मुताबिक, इस मामले में



01-01-1951 - 08-10-2026

मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) दर्ज किया गया है और नाना पाटेकर के

निधन की चिकित्सकीय वजह की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया

अलविदा  
नाना

जाएगा।

नाना पाटेकर के निधन की खबर

सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है। उनका फिल्मी सफर चार दशक से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1978 में फिल्म 'गमन' से की थी। अपने अभिनय से उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बनाई। 'परिदा', 'अंगार', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर', 'अग्निसाक्षी', 'अब तक छपन', 'अपहरण', 'वेलकम' और 'नटसम्राट' जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। फिल्म 'क्रांतिवीर' में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने करियर में उन्होंने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

## रुस-यूक्रेन युद्ध में भारत की नई पहल: ट्रंप जो न कर सके, अब दिल्ली बनाएगी मुमकिन

**नई दिल्ली (ए)।** रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को अब चार साल से अधिक का समय जा चुका है, इस जंग ने लाखों लोगों की जान ली है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का गंभीर प्रभु से बाधित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने के लिए अपने दूसरे कार्यकाल में कई कूटनीतिक और धमकी भरे प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब इस खूनी जंग को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण शांति प्रस्ताव दिया है।

दरअसल प्रस्ताव भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने 3 सितंबर को यूक्रेन की अपनी पहली स्वतंत्र यात्रा के दौरान पेश किया, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और भारत की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत का यह तीन-सूत्रीय प्रस्ताव युद्ध के सबसे संवेदनशील और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है।भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक



ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकना है। दोनों पक्षों से एक-दूसरे के एनर्जी प्लांट्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने की अपील। इसके अलावा ब्लैक सी के बंदरगाहों से अनाज और ऊर्जा की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। इतना ही नहीं ब्लैक सी में आवाजाही करने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले को तुरंत रोकना।

भारत का यह प्रस्ताव अब तक आए अन्य देशों जैसे मिस्र और तुर्की (जो मुख्य रूप से व्यापारिक जहाजों पर केंद्रित थे) और अमेरिका (जो एनर्जी सीजफायर

पर केंद्रित था) के प्रस्तावों की तुलना में अधिक व्यावहारिक और व्यापक माना जा रहा है। भारत ने इन सभी प्रमुख चिंताओं को एक साथ रखकर एक समग्र समाधान प्रस्तुत किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में इस युद्ध को रोकने के लिए अथक प्रयास करते रहे, कभी धमकियां दीं तो कभी बातचीत का सहारा लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब भारत की यह पहल न केवल वैश्विक शांति के लिए एक नई उम्मीद जगाती है, बल्कि उस जटिल चुनौती का समाधान खोजने का प्रयास करती है, जिसमें एक वैश्विक शक्ति विफल रही।

## राहुल-अखिलेश साथ प्रदर्शन के बाद खरगो के भोज से नदारद रहे सपा नेता

**नई दिल्ली(ए)।** लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में अदरूनी समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजधानी में हुए प्रदर्शन में एक साथ नजर आए। हालांकि, आले ही दिन बुधवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी नेताओं के लिए भोज का आयोजन किया, तो उसमें सपा नेता शामिल नहीं हुए। इस भोज में शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता भी शामिल नहीं हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव और सपा नेताओं की गैर-मौजूदगी की रही।

यह भोज राजधानी के जनपथ पर स्थित एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य आगे की रणनीति पर चर्चा करना था। सपा नेताओं की अनुपस्थिति के बाद, कांग्रेस को कुछ ही समय में इस पर सफाई जारी करनी पड़ी। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आई कि



पर ही पूरा फोकस रहा। हालांकि, सपा ने इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। पार्टी के एक नेता ने अनौपचारिक रूप से बताया कि वे आकाशवाणी भवन के संबंध में कांग्रेस के कमजोर समन्वय से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि यह गांधी परिवार का नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक का एक साझा प्रदर्शन होना चाहिए था। नेता ने यह भी कहा कि देश का अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जहां समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी कहीं अधिक है। अखिलेश यादव ने उत्तर

प्रदेश में एसआईआर (संविधान, संस्थाएं, आरक्षण) के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व ने सिर्फ सांकेतिक कदम उठाए। दिल्ली में कांग्रेस यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सिर्फ वही एसआईआर को लेकर गंभीर है। सपा के एक सांसद ने भोज में शामिल न हो पाने का एक और कारण देर से न्योता बताया। उनके अनुसार, मंगलवार शाम प्रदर्शन के बाद अधिकांश सांसद अपने क्षेत्रों में लौट गए थे और तब तक भोज के बारे में कोई सूचना नहीं थी। यदि समय पर जानकारी मिलती, तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव या वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के सांसदों या जो दिल्ली में मौजूद थे, उन्हें भोज में शामिल होने के लिए कह सकते थे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि आज के भोज के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भोज का फैसला देर रात लिया गया और उसी समय इसकी जानकारी दी गई।

## आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची से हटाए गए 46 लाख नाम

**हैदराबाद(ए)।** एनडीए शासित राज्य आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग गुरुवार, 8 अक्टूबर से राज्य में एक विशेष अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत, ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 46.62 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति का दोबारा सत्यापन घर-घर जाकर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और सभी योग्य नागरिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, बृथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों से संबंधित 46,62,583 हटाए गए मतदाताओं की सूची लेकर घर-घर जाएंगे और उनकी वास्तविक स्थिति का दोबारा सत्यापन करेंगे। यह विस्तृत जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 15 जून से 24 जुलाई के बीच हुई गणना के बाद 44.8 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। अधिकारियों को ये लोग उनके दर्ज पते पर नहीं मिले थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि सत्यापन के दौरान यह सामने आता है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो उसे फॉर्म-6 भरने में पूरी मदद की जाएगी। जरूरी सत्यापन के बाद उसका नाम निरंतर अपडेट प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। विवेक यादव ने जोर देकर कहा कि आयोग का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को बाहर रखना है। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नोटिस प्रक्रिया के दौरान 6 अक्टूबर तक 1.73 लाख और मतदाता ऐसे पाए गए, जो अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र नहीं थे। इन नामों को भी हटया जाएगा। आंध्र प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 16 अक्टूबर को प्रकाशित की जानी है। इससे पहले, बीएलओ की घर-घर जाकर की गई गणना के बाद मृत, दूसरी जगह जा चुके और एक से अधिक जगह दर्ज मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, जिसके बाद 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इस ड्राफ्ट सूची में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ से अधिक थी। एसआईआर 2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वहीं, वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए अगले वर्ष की 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख माना जाता है। 16 अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम सूची में अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूट जाता है, या बाद की किसी क्वालिफाइंग तारीख पर कोई व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य होता है, तो वह निरंतर अपडेट प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-6 जमा कर सकता है।

## यूपी में नकली और पुराने नोटों के नेटवर्क का भंडाफोड़

**हापुड़(ए)।** उत्तर प्रदेश में जाली करेंसी और पुराने, बंद हो चुके नोटों के बड़े पैमाने पर नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हाल ही में जहां एक ओर बैंकों में 17 करोड़ से अधिक के नकली नोटों की जांच चल रही है, वहीं अब हापुड़ में 1.43 करोड़ रुपये मूल्य के पुराने, बंद हो चुके नोट बरामद किए गए हैं। हापुड़ देहात पुलिस ने यह बड़ी सफलता तत्तारपुर चौकी क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हासिल की, जब चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोक़ा गया। पुलिस के रोकने पर युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर उसे धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से भारी मात्रा में बंद हो चुके पुराने नोटों के बंडल बरामद हुए, जिनकी कुल धनराशि करीब 1.43 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पुलिस ने तत्काल युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर और हाल निवासी नंद ग्राम के देवेंद्र के रूप में हुई है। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि उनकी टीम बहनो की जांच कर रही थी, जब यह संदिग्ध पकड़ा गया। नोटबंदी के कई साल बाद इतनी बड़ी संख्या में पुराने नोटों की बरामदगी से प्रशासन और जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह भारी-भरकम धनराशि किसकी है, और इन बंद हो चुके नोटों को बदलने या खपाने के पीछे क्या योजना थी। पुलिस इस बात पर भी पैनी नजर रख रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है, जो ऐसे नोटों को बाजार में फिर से लाने का प्रयास कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयरकर विभाग और अन्य संबंधित वित्तीय जांच एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। विभिन्न बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी में 17 करोड़ से अधिक के नकली नोटों के जखीरे की जांच अभी भी जारी है।

## संयुक्त राष्ट्र में भारत का ओआईसी पर तीखा प्रहार: पीड़ित-दोषी में फर्क समझें

**नई दिल्ली,(ए)।** संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में भारत की आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों पर की गई टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया, यह कहकर कि यह समूह पीड़ित और दोषी के बीच फर्क करने में असमर्थ है। पश्चिम त्रिपुरा से लोकसभा सदस्य बिप्लव कुमार देब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन के उपाय विषय पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देकर ओआईसी को कड़ी नसीहत दी।

लोकसभा सदस्य देब ने जम्मू-कश्मीर के उल्लेख पर कड़ी आपत्ति जताकर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई उन्हीं स्थानों से निर्देशित और योजनाबद्ध हमलों का जवाब थी। ओआईसी पर तथ्यों और कल्पनाओं के बीच अंतर न कर पाने का आरोप लगाकर उन्होंने कहा कि भारत को सीमा पर आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने ओआईसी द्वारा जम्मू-कश्मीर के अनुचित उल्लेख की आलोचना कर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले रावलकोट पर ध्यान देने की सलाह दी, जहाँ अंधाधुंध हत्याएं और मानवाधिकारों का हनन स्पष्ट है। ओआईसी ने अपने बयान में



दक्षिण एशिया में सैन्य तनाव बढ़ने और पाकिस्तान में अनुचित हमलों का जिक्र किया, पर भारत का नाम नहीं लिया। भारत ने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान और पीआरके में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया था। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए जघन्य आतंकवादी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, का सीधा जवाब थी। हमला पाकिस्तान स्थित द रेंजिस्ट्रेस फ्रंट ने किया था। देब ने भारत के कड़वे अनुभव को साझा कर कहा कि आतंकवाद एक लगातार और रोजमर्रा की वास्तविकता है। उन्होंने जोर दिया कि इसका हर रूप मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है, जो शांति,

प्रगति और मानवाधिकारों को प्रभावित करता है। स्पष्ट किया कि अच्छे-बुरे आतंकवाद में कोई फर्क नहीं लिया। भारत ने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान और पीआरके में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया था। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए जघन्य आतंकवादी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, का सीधा जवाब थी। हमला पाकिस्तान स्थित द रेंजिस्ट्रेस फ्रंट ने किया था। देब ने भारत के कड़वे अनुभव को साझा कर कहा कि आतंकवाद एक लगातार और रोजमर्रा की वास्तविकता है। उन्होंने जोर दिया कि इसका हर रूप मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है, जो शांति,

वैश्विक आतंकवाद-रोधी प्रयासों की प्रमुख कमी के तौर पर 1996 में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) के लागू न होने का उल्लेख किया। देब ने दोहराया कि सीसीआईटी को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने से कानूनी ढांचा मजबूत होगा।

## रुस और ईरान पर अमेरिकी दांव उल्टा पड़ा, भारत ने दुकराई फ्री ट्रेड डील

**नई दिल्ली,(ए)।** अमेरिका का भारत पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने का दांव पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। रूस और ईरान पर शिकंजा कसने के बहाने भारत-रूस संबंधों को निशाना बनाने चली अमेरिकी प्रशासन की नीतियों ने खुद भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड डील की बलि ले ली है। पारबंदियों की तलवार लटकाकर व्यापार समझौते की उम्मीद कर रहे अमेरिका को भारत ने कड़ा संदेश दिया है और दबाव में आकर कोई भी सौदा करने से साफ इनकार कर दिया है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को धमकियों से झुकाने की वॉशिंगटन की पुरानी नीति अब पूरी तरह उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक कानून का सहारा लिया था, जिसका मुख्य मकसद भारत और रूस की दशकों पुरानी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती में दरार डालना था।

अमेरिका चाहता था कि भारत किसी भी कीमत पर रूस से कच्चा तेल और रक्षा उपकरण खरीदना बंद कर दे। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया था कि वह रूस से व्यापार करने वाले देशों के सामान पर भारी-भरकम पेनल्टी टैरिफ लगा सकते हैं। वॉशिंगटन को लगता था कि वह इस आर्थिक डर का इस्तेमाल करके भारत को अपने पाले में झुका लेगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के मामले में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका का यह रुख न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि उसकी कूटनीतिक नाकामी और दोहरे मापदंडों को भी बेनकाब करता है। जमीनी हकीकत यह है कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान भारत ने ही अमेरिकी ऊर्जा बाजार को एक बड़ा संबल दिया है और हाल के महीनों



था कि वह रूस से व्यापार करने वाले देशों के सामान पर भारी-भरकम पेनल्टी टैरिफ लगा सकते हैं। वॉशिंगटन को लगता था कि वह इस आर्थिक डर का इस्तेमाल करके भारत को अपने पाले में झुका लेगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के मामले में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका का यह रुख न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि उसकी कूटनीतिक नाकामी और दोहरे मापदंडों को भी बेनकाब करता है। जमीनी हकीकत यह है कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान भारत ने ही अमेरिकी ऊर्जा बाजार को एक बड़ा संबल दिया है और हाल के महीनों

में भारत अमेरिकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। इसके बावजूद अमेरिका द्वारा भारत को निशाना बनाया जाना समझ से परे है, जबकि रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा आयात करने वाले अन्य देश भी शामिल हैं जिन पर अमेरिका का रवैया नरम रहता है। अमेरिका की असल मंशा यह है कि भारत अपने कृषि, डिजिटल और औद्योगिक क्षेत्रों को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारत के लिए अपने करोड़ों किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

## राहुल और दीपके के आंदोलनों में बढ़ी खींचतान, चुनाव आयोग पर आरोपों का नया दौर

**नई दिल्ली(ए)।** हाल के वर्षों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर बोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। उनके इन आरोपों को उस समय और बल मिला जब एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति का दावा किया गया। हालांकि, चुनाव आयोग ने बिना देरी किए इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन नीट पेपर लीक आंदोलन से सुविधियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को तुरंत भुनाने की कोशिश की। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी और तत्काल आंदोलन का ऐलान कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस के मुद्दे भले ही एक जैसे हों, लेकिन दोनों ही दल एक-दूसरे का खलकर साथ देने से कतरा रहे हैं। अभिजीत दीपके जब जंतर-मंतर पर धर्मंद प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर विपक्षी दलों को भी चौंका दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के इस कार्यक्रम की चर्चा बाकी विपक्षी दलों से नहीं की गई थी। बाद में उन्होंने धर्मंद प्रधान के इस्तीफे का श्रेय लेने की भी कोशिश की, हालांकि कई विपक्षी दल इसे कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके की ही जीत मानते हैं। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस मामले पर कोई भी चूक करना नहीं चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ तमाम विपक्षी दल 2014 में केंद्र में भाजपा के आने के बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते आ रहे हैं। उनका दावा है कि ईवीएम के जरिए वोटों की हेराफेरी की जाती है। हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को लगातार झुठलाता रहा है। अब जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस अपने उन पुराने आरोपों के दम पर इस आंदोलन को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती

